

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत

डॉ. प्रियंका मिश्र,

हिन्दी विभाग,
दूर शिक्षा निदेशालय,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
वर्धा (महाराष्ट्र).

‘मेक इन इंडिया’ की अवधारणा वर्तमान दौर में वैश्विक परिदृश्य में एक नवीन सोच की परिचायक है। समाज और देश की विकराल समस्या ‘बेरोजगारी’ और उससे उभरे मानव मन को और मानव मस्तिष्क के भटकाव को मानने के साहसिक सद्प्रयास का ही परिणाम है ‘मेक इन इंडिया’। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो महंगाई विकास की सूचक होती है। वैश्विक पटल पर समग्र देश अपनी राष्ट्रीय अनुपलब्ध आवश्यकताओं की पूर्ति आयात के माध्यम से पूरी करते हैं और अनिश्चित वस्तुओं का निष्पादन निर्यात करके, अपनी राष्ट्रीय आय को संतुलित करके पूरा करते हैं। अगर किसी देश का आयात निर्यात के मुकाबले अधिक होता है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था में असंतुलन आ जाता है जिसके फलस्वरूप आयातक देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाती है और यही से आरम्भ होता है महंगाई का खेल।

कृषि प्रधान मौसमी कार्यों से बचा हुआ अतिरिक्त समय के समायोजन को ही ध्यान रखते हुए राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी ने कुटीर उद्योग और स्वदेशी का सपना देखा और उसका ताना बाना बुना, हर हाथ को काम उनका वास्तविक उद्देश्य था। यह उत्कृष्ट विचार महान युग द्रष्टा की आँखों में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौंधा था और संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बीत चुके हैं इस

दौरान गाँधी तो भारतीय समाज की चेतना में विद्यमान रहे किन्तु गाँधी के विचार और उनकी चिन्तनधाराओं को राजनीति और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर हाशिए पर धकेल दिया गया। 2 अक्टूबर और 30 जनवरी तथा कुछ अन्य दिनों में महात्मा गाँधी और उनके विचार अचानक उभर कर आते और फन: किताबों से अलमारियों में बंद हो जाते। कालानुक्रम में गाँधी राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण ढाल के रूप में तो स्थापित हुए किन्तु राजनीतिक इच्छाशक्तियों की कमी के कारण उनके विचार बढ़ते और बदलते भारत में गौण होते चले गए। इसी का परिणाम रहा कि भारत का समाज दो हिस्सों में बँटता चला गया। एक वह भारत जो सुदूर गाँवों में अभावग्रस्त, अशिक्षित तथा अंधकारमय ज़िन्दगी जीने का अभिशप्त था वहीं दूसरा भारत वह था जो समानान्तर ‘इंडिया’ में रहने वाले संभ्रांत वर्ग, पूंजीपति वर्ग, उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग के रूप में स्थापित था। जहाँ यह वर्ग भारत अथवा विश्व के कुलीन शिक्षा संस्थानों में शिक्षित होता है वहीं बाकी भारत सरकारी दमघोंटू नाम मात्र के विद्यालयों में शिक्षा का ककहरा पढ़ रहा है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ये सरकारी संस्थाना आनुपातिक क्रम में निजी एवं कुलीन शिक्षा संस्थानों की अपेक्षाकृत बदतर स्थिति में हैं। इन शिक्षण संस्थानों में ही वास्तविक भारत का निर्माण होता है। भारत यहीं शिक्षित होता है, यहीं मजदूर बनता है, यहीं असंगठित क्षेत्रों की ज़िन्दगी के बोझ को ढोता है

और एक उम्र के बाद युवा होते हुए भी बुढ़ापे की झुर्रियों के साथ वह अपनी जिन्दगी की कहानी लिखता है।

विगत वर्षों में अनेक केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने वास्तविक भारत, जोकि गाँवों में बसता है और भारत के निर्माण में सबसे अधिक योगदान देता है, की समस्याओं को जानने और उन्हें दूर करने का प्रयास तो किया किन्तु अधिकांश समस्याएं आज भी समाज में जस-की-तस हैं। विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक, प्राकृतिक एवं सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं को लेकर वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने जिस प्रकार की प्रतिबद्धता दिखाई है वह उल्लेखनीय है। यह एक काल्पनिक अवधारणा है कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए पूँजी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। सत्य तो यह है कि राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में पूँजी एक सहायक बिन्दु है। राष्ट्र का विकास तो तभी सम्भव होता है जब उसमें समाज के सभी वर्गों की समान हिस्सेदारी हो। भारत के सम्बन्ध में तो यह ओर भी अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ का समाज भाषाओं, जातियों, वर्गों और संस्कृतियों की विराटता में जीता है। जहाँ इन सबके भीतर द्वंद्व की स्थिति है वहीं इन सबमें प्रेम और सद्भाव का सामंजस्य भी है। इसीलिए भारत इन सबके भीतर समान रूप से बसता है। इन सभी में एक समान भारतीय स्थिति यह है कि किसान, गरीब और मजदूर वर्ग जैसे वंचित भारतीयों की समस्याएं इनमें समान रूप से व्याप्त हैं। शायद यही कारण है कि वर्तमान सरकार ने भारत के विकास की ओर बढ़ते हुए कदमों में इस वर्ग को अपना सबसे बड़ा सहभागी स्वीकार किया। सरकार जानती है कि इस वर्ग के विकास के बिना भारत का विकास सम्भव ही नहीं।

रूस के मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा था कि आने वाले समय में किसी देश का महत्व सामाजिक सम्बन्ध से नहीं, बाज़ार से आँका

जाएगा। भूमण्डलीकरण ने गोर्बाचेव के इस कथन को सत्य भी कर दिया। बाज़ार ने विश्व समाज को ही नहीं बल्कि उसकी संस्कृति को अपने दायरे में कैद कर लिया। भारतीय संस्कृति भी बाज़ार की इस चकाचौंध से अछूती न रही। बाज़ार ने भारतीय संस्कृति के सबसे प्रबल पक्ष भारतीय पर्वों को भी नहीं बक्शा। अंग्रेज़ों ने जिस तरह से भारतीय लघु उद्योग-धंधों को समाप्त कर भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया वही भूमण्डलीकरण की इस बाज़ारवादी आँधी ने भी करना आरम्भ कर दिया। लेकिन भारत के गाँवों में गरीबों और मजदूरों ने भारतीय संस्कृति को संरक्षित कर उसे बाज़ार के हाथों का खिलौना नहीं बनने दिया। इसी कारण वर्तमान भारतीय सरकार ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण को प्राथमिक आधार मानते हुए 'मेक इन इंडिया' जैसी अवधारणा को भारतीय समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया।

मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह शब्दों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। भारत की विभिन्न योजनाओं में से एक 'मेक इन इंडिया' इसका सबसे महत्त्वपूर्ण रूप है। शिक्षित और अशिक्षित समाज को एक ही दिशा की ओर ले चलने का कार्य करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के वंचित समाज की श्रम साधना का सम्मान किया। इस दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार ने भारत की सभी समस्याओं के निराकरण के लिए भारत को डिजिटल युग की डिजिटल क्रांति के साथ सम्बद्ध किया। श्रमिकों और खरीदारों के बीच दलालों की भूमिकाओं को समाप्त करते हुए सीधे बाज़ार के साथ जोड़ने की यह पहल भारत के गरीब वर्ग की समस्याओं को खत्म करने का मजबूत आधार बनी।

'मेक इन इंडिया' की अवधारणा का वास्तविक अर्थ किसी 'एक दिशा' की ओर नहीं है। यूँ कहें कि यह केवल एक शब्द-समूह नहीं है बल्कि 'विज़न' है। एक ऐसी दृष्टि जो समाज

के साथ-साथ राष्ट्र को भी उन्नति और प्रगति के पथ पर ले चलने में सक्षम तो होगी ही, वहीं वैश्विक रूप से भारतीय कलाओं को भी प्रतिष्ठा दिलाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस 'मेक इन इंडिया' के 'मेक' में सबकी भागीदारी शामिल है, चाहे वह शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, अमीर हो अथवा गरीब, साधन-सम्पन्न हो अथवा सुदूरभारतवासी जो संसाधनों के अभाव में दुरुह जीवन जीने को बाध्य होकर इन सभी की कार्यक्षमताओं का दोहन और उसके श्रम का वास्तविक मूल्य उसे प्राप्त हो सके, यह भारत सरकार की इस योजना की वास्तविक लक्षित-दृष्टि है।

जिस तरह से चीन की सरकार ने अपने देश में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन और उसे बाजार प्रदान करने की योजना वर्षों से चला रखी है, वर्तमान भारत सरकार की सोच उससे कहीं अधिक आगे की सोच है। इस योजना में भारतीयों की योग्यता और उनकी कलात्मक प्रतिभाओं को विकसित करने के साथ-साथ उन्हें बाजार तक पहुँचाने की योजना तथा प्रतिभा पलायन को रोकना भी सरकार का मकसद है। इतना ही नहीं विश्व में भारत की सांस्कृतिक छवि को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भुनाकर जिस तरह भारतीय मुद्रा विदेशों में जा रही है उसे रोकना और विदेशी मुद्रा से भारतीय मुद्रा भण्डार को भरना भी इसका एक लक्ष्य है। हो सकता है कि एक सामान्य नागरिक या विपक्ष की दृष्टि में यह योजना केवल एक योजना भर हो लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने तथा उसे ओर अधिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में बढ़ाया गया एक सशक्त कदम भी है।

महात्मा गाँधी ने भारत की स्वतंत्रता के उपरान्त कहा था कि यदि भारत का विकास करना है तो भारत की शोषित और गरीब जनता के श्रम के साथ-साथ स्वदेशी भावना पर भी

अपनी निर्भरता बढ़ानी होगी। अर्थशास्त्रियों का मत है कि मनुष्य केवल मुँह और पेट लेकर पैदा नहीं होता, उसके पास ईश्वर के वरदान स्वरूप दो हाथ-पैर तथा दिमाग भी होता है। उसके पास उपलब्ध कार्यक्षमताओं का दोहन कैसे किया जाए, जो राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो, इस बात की व्यवस्था और माहौल का निर्माण तो सरकार को ही करना होगा। लेकिन इस देश ने गांधी के सपनों के भारत को जैसे भुला ही दिया। विभिन्न सरकारों की नीतियों की कार्यप्रणाली के कारण पूँजीपति ओर अधिक पूँजी-सम्पन्न होते चले गए और गरीब क्षमताओं के होते हुए भी, संसाधनों के अभाव में ओर अधिक गरीब होता चला गया। लेकिन 'मेक इन इंडिया' योजना ने कोरपोरेट घरानों की एकछत्र राज करने की इच्छा को जैसे धराशायी कर दिया। सरकारी अनुदानों, सहायताओं और छूटों के साथ विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कोरपोरेट घरानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जैसे अपने हाथों में ले लिया। कहीं-न-कहीं राजनीति भी इस व्यवस्था के लाभ का हिस्सा बनी। एक ओर तो किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर कोरपोरेट घरानों को भारत के विकास के नाम पर सस्ते में दे दिया गया वहीं किसान प्राकृतिक आपदाओं और सरकारी उपेक्षाओं का शिकार होकर आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो गया।

विगत वर्षों का इतिहास उठाकर देखें तो भारत की सभी सरकारों ने प्रत्येक वर्ष के बजट में सबसे अधिक पैसा भारत की सुरक्षा के नाम पर रखा। रक्षा क्षेत्र में विदेशी सामानों की खरीद और उनमें होने वाले घोटालों के चलते अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ऐसे में 'मेक इन इंडिया' जैसी योजना ने इस दिशा में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरबों की लागत से खरीदे गए सुरक्षा उपकरणों और अन्य उपकरणों के निर्माण भारत में करने की सोच के चलते जहाँ भारत को आर्थिक रूप से मजबूती मिली वहीं भारत में ही निर्मित

सुरक्षा यंत्रों की गोपनीय तकनीक के कारण भारत की सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक सशक्त हुई। इतना ही नहीं भारत सुरक्षा-उपकरणों के बाज़ार में उपभोक्ता के बजाए विक्रेता की भूमिका में भी आ गया। गत वर्ष भारत ने भारतीय विज्ञानों द्वारा निर्मित रॉकेट को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना में लगभग चार हजार करोड़ों रुपए बचाने के साथ-साथ अनेक देशों के सैटेलाइट्स को उपग्रह में भेजने के लिए धन प्राप्त कर अपने को सम्पन्न भी बनाया। अमेरिका जैसे देशों में जिस रॉकेट को बनाने की लागत रु.4500/- करोड़ आई वहीं भारत ने उस रॉकेट को केवल रु. 450/- में बनाकर इस क्षेत्र में अपनी पहचान को भी स्थापित किया। वहीं रक्षा क्षेत्र के बजट में सुरक्षा उपकरणों को खरीदने में लगने वाले पैसे को वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा सुरक्षा के निमित्त होने वाले शोध-कार्यों पर खर्च कर उन्हें साधन समपन्न बनाने की ओर कदम बढ़ाया। डी. आर.डी.ओ. जैसे संस्थान जो अभी तक धन की कमी के बावजूद नई-नई तकनीकों को विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, 'मेक इन इंडिया' की योजना ने उनकी धन की कमी को दूर करने के साथ-साथ उन्हें अधिक सशक्त भी बनाया।

वैसे भी सरकारी खरीद चाहे वह हथियारों के क्षेत्र में हो, विमानों के क्षेत्र में हो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो हस्तांतरण वस्तुओं का नहीं वरन् तकनीक का होना चाहिए। भारतीयों की मेधा विश्व में जहाँ तकनीकी क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है वहीं भारत उस तकनीक से वंचित है। यदि उस तकनीक का ही हस्तांतरण भारत को हो जाए तो निश्चित रूप से वस्तुओं के भारत में निर्माण का रास्ता इतना सहज होगा कि भारत अपने साथ-साथ विश्व की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा सकेगा। भारत की अधिकांश जनता इस समय युवा वर्ग की है। यदि इस युवा वर्ग को तकनीक के साथ जोड़कर उसे संसाधनों की उपलब्धता कराई जाए तो निश्चित रूप से

प्रकारांतर में यही युवा वर्ग अपने साथ-साथ राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों को भी सम्पन्न बनाने में अपना योगदान दे सकेगा।

वैश्विक उदारीकरण के दौर में जब पूरा विश्व एक गाँव के रूप में तब्दील हो चुका है, प्रतियोगिताएं सिर्फ प्रतियोगी बनने के लिए आयोजित हों, गुणवत्ता गौण हो चली हो तो भारतीय बाज़ार और भारतीय समाज को स्थायित्व दिलाने के लिए भारतीय पक्ष में नीतियों को सृजित करना ही होगा, अन्यथा भारतीय बाज़ार और सामान, किसानों द्वारा अतिरिक्त उत्पादित आलू की भांति जैविक खाद ही बनता रहेगा। भारतीय बाज़ार एवं भारत निर्मित उत्पादन को पहले भारत में गौरवान्वित करना होगा, यह काम जनता के स्तर पर नहीं बल्कि सरकारी स्तर और नीति निर्माण से ही सम्भव हो सकता है। हमारा बाज़ार जब तक बाहरी गुणवत्ताहीन सामानों से अटा-पटा रहेगा, भारतीय उत्पादों को वह गौरव हासिल हो ही नहीं सकता क्योंकि शिक्षित और कम शिक्षित लोगों के मानस-पटल पर डॉलर और इम्पोर्टेड ब्रांड की छवि इस तरह से अंकित है कि उनकी दृष्टि में भारतीय सामान गुणवत्ताहीन सामान बन जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत के गौरव को भारत और विश्व दोनों में ही समान रूप से बनाना होगा। 'मेक इन इंडिया' को केवल एक विचार की भांति देखना भर नहीं होगा वरन् उसे क्रियान्वित कर समूचे भारत की जनता को इससे सम्बद्ध करना होगा। वैसे भी विश्व में शक्ति-सम्पन्न देशों का ही दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है। यदि भारत अपनी तकनीकी के माध्यम से अपने देश का निर्माण और उसकी सुरक्षा में सक्षम होगा तो विश्व का कोई देश भारत की ओर टेढ़ी दृष्टि करने में भी अनेक बार सोचेगा। क्योंकि जब तक भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक वह दृढ़ रूप से अपने पाँव अपनी ही धरती पर जमाकर नहीं रख सकेगा। आवश्यकता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन इस रूप में हो कि वह

प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके तभी सरकार का अस्तित्व अंगद के पैर सरीखा बन सकता है।

आखिर पूरी दुनिया में डिजिटल क्रांति को फैलाने वाली कम्पनी माइक्रोसोफ्ट में 70 प्रतिशत इंजीनियर भारतीय होने के बावजूद भी भारत को डिजिटल दुनिया से जुड़ने में इतना वक्त क्यों लगा? आखिर क्यों इन आई.टी. तकनीकी विशेषज्ञों को भारत में वे संसाधन उपलब्ध नहीं हो सके, वे आर्थिक पैकेज नहीं मिल सके जिससे वे भारत को विश्व गुरु सरीखी पहचान फन: दिला पाने में समर्थ हो सकते? कहीं-न-कहीं हमें इस सच को स्वीकार करना ही होगा कि हम आत्मनिर्भर बनने की बजाए दूसरों पर निर्भर होते चले गए। वर्तमान सरकार ने भारत के प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिन योजनाओं को लागू किया उनसे कहीं-न-कहीं भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। डिजिटल होती दुनिया के साथ अपने सम्बन्धों को नया अध्याय लिखने के लिए वर्तमान भारत सरकार ने भारत को डिजिटल दुनिया को सबसे प्रभावशाली हिस्सा बना दिया। एक ओर तो यह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें बाज़ार के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है वहीं बदलती हुई दुनिया के साथ सामंजस्य बिटाने के लिए वह तकनीकी के क्षेत्र के साथ अपने कदम-से-कदम मिलाकर भारत को आगे बढ़ा रही है। परम्परा और आधुनिकता का यह सामंजस्य भारतीय समाज को फन: विश्व में विश्व-गुरु के पद पर आसीन करने की ओर बढ़ाया गया मजबूत और दिशाबद्ध कदम है।

भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है इसका तात्पर्य यह नहीं कि भारत शांतिप्रिय नहीं है। शांति और अहिंसा की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हमें अपने को सुरक्षित रख पाने में समर्थ हों। हमारा निर्माण बाज़ार के लिए नहीं बल्कि समूची मानव सभ्यता के विकास

और उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए 'मेक इन इंडिया' का वास्तविक उद्देश्य इस देश की युवा पीढ़ी को उस दिशा में ले जाना है जहाँ उसे शिक्षा नौकर न बनाकर मालिक बनाए। यानि वह इतना आत्मनिर्भर हो कि रोजगार की तलाश में जाने की बजाए दूसरों को रोजगार दे पाने में समर्थ हो। वह उद्यमशील बने और अपने उद्यमों में शेष वंचित भारत को रोजगार दे। जिस दिन 'मेक इन इंडिया' की यह योजना युवा भारत को आत्मनिर्भर बना देगी उस दिन भारत के विकास की यह महायात्रा पूर्ण रूप से सफल होगी। भारत के निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के विकास की इस महायात्रा के रथ के सारथी के रूप में इंडिया और भारत के बीच की विभाजक मोटी लकीर को मिटाकर विकास की ओर बढ़ने का जो बीड़ा उठाया है निश्चित रूप से युवा भारत विश्व में भारत को फन: विश्व गुरु बनाकर दिखाएगा।

संदर्भ

1. चौहान, विनोद (2021), कल्पवृक्ष नरेन्द्र मोदी, संकल्प प्रकाशन, छत्तीसगढ़ (ISBN-978-93-90720-24-8)
2. अय्यर, परमेश्वरन (2020), स्वच्छ भारत क्रांति, डायमण्ड पॉकेट बुक्स प्रा. लि., दिल्ली (eISBN-978-93-9028-761-1)
3. यहाँ पे आपका यूनिकोडशुक्ल, रजनीश कुमार (2021) भारतीय ज्ञान परंपरा और विचारक, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली (eISBN 978-93-90378-14-2)
- 4- नेम, अशोक कुमार (2020) मोदी रू एक प्रेरक कथा, न्यू अशोका पब्लिकेशन्स, जबलपुर, (ISBN 978-81-954176-2-9)
5. खरे, मनीष (सं।) (2020), भारत में शिक्षा नीति की दश और दिशा, श्री विनायक पब्लिकेशन्स, आगरा (ISBN 978-93-912672-30)